ग्रामोद्योग अयोग, खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, संस्थान तथा संस्थानों के संघ के साथ संयुक्त रूप से कच्चे माल की आपूर्ति, विपणन सहायता, प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रौद्योगिकी सुधार, औद्योगिक संपदा की स्थापना इत्यादि के रूप में सहायता सेवाओं का जाल फैला रही है। अपने सामान्य कार्यक्रम के अतिरिक्त खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने 125 ब्लॉक विकास कार्यक्रम, जिला विशेष रोजगार कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय कार्यक्रम में मधुमक्खी पालन, हस्तनिर्मित कागज तथा चमड़ा जैसे विशेष कार्यक्रम भी चलाये हैं। बिहार में के वी आई योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 125 ब्लॉक कार्यक्रम के अधीन 11 ब्लॉकों को चुना गया है तथा जिला विशेष रोजगार कार्यक्रम के अधीन 4 जिलों को चुना गया है।

Annual growth in the industrial sector

3841. DR. B.B. DUTTA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government are committed to maintain a 12% annual growth in the industrial sector;

(b) the growth rate of industrial production during the Sixth, Seventh and Eighth Five Year Plan;

(c) in what manner Government propose to achieve the 12% growth rate; and

(d) the details of measures taken in this regard so far?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) and (b) The Common Minimum Programme of the Government has envisaged maintaining industrial growth at 12%. The growth rate of industrial production during Sixth, Seventh and Eighth Five Year Plan stood at 5.9%, 8.5% and 7.3% (expected).

(c) and (d) Sector specific strategies have already been initiated to remove constraints in under performing sectors. The credit policy announced recently by Reserve Bank of India is also expected to provide further impetus to industrial growth. Government has also proposed initiatives in the Union Budget 1997-98 for accelerated industrial growth. Domestic and foreign investment is encouraged in industry and infrastructure sectors.

Privatisation of BHEL and SAIL

3842. PROF. RAM KAPSE: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government have a proposal for privatisation of Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) and Steel Authority of India Limited (SAIL) under consideration;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the specific reasons for privatisation of these two Government companies?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

उद्योगों की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्राप्त होना

3843. **श्री शिव चरण सिंह:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान देश में उद्योग स्थापित करने के लिए विदेशों से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) इस संबंध में संयुक्त उद्यमों सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें राज्य-वार कितना-कितना निवेश किये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) क्या देश में इन उद्योगों की स्थापना से समग्रत: निकलने वाले परिणामों के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (ग) 1 अगस्त, 1991 से 31 दिसम्बर, 96 तक की अवधि के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निदेश के कुल 10119 (वित्तीय तकनीकी) प्रस्ताव अनुमोदित किये गए हैं जिनमें 95591.71 करोड़ रुपये की राशि अन्तर्ग्रस्त है। इन विदेशी सहयोग संबंधी प्रस्तावों के राज्य वार ब्यौरे विवरण में दिये गए हैं। **(नीचे देखिए)**।

ऐसे प्रस्तावों के ब्यौरे अर्थात् विदेशी सहयोगी का नाम तथा देश, अन्तर्ग्रस्त इक्विटी निवेश, विनिर्माण की मद/कार्यकलाप भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा मासिक न्यूजलेटर के पूरक के रूप में प्रकाशित किये जाते हैं और इनकी प्रतियां नियमित रूप से संसद की लाइब्रेरी को भेजी जाती हैं।

(घ) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ने परियोजनाओं के क्रियान्वयन का पता लगाने के लिए एक अध्ययन शुरू किया है।